खाद्य तेलों का आयात

1846. **श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान प्रति-वर्ष कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया;

(ख) किन-किन देशों से कौन-कौन से खाद्य तेलों का आयात किया गया;

(ग) इन खाद्य तेलों के आयात में राज्य व्यापार निगम को किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत कितना घाटा उठाना पड़ा और साथ ही राजकोष से कितनी राशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई गई; और

(घ) खाद्य तेलों के आयात में होने वाले घाटे के क्या कारण हैं और इन घाटों को कम करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) 1994-95 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य व्यापार निगम ने केवल सरकारी खाते पर इंडोनेशियाई और मलेशियाई मूल के आर० बी० डी० पामोलीन का आयात किया था। उक्त अवधि के लिए आर० बी० डी० पामोलीन के आयात के अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	आर० बी० डी० पामोलीन का आयात		
	मलेशिया से	इंडोनेशिया से	जोड़
1994-95	0.81	0.26	1.07
1995-96	1.66	0.36	2.02
1996-97	1.43	0.06	1.49
1997-98	0.48	0.41	0.89

(ग) सरकारी खाते पर किए गए खाद्य तेल के आयात और हैंडलिंग के संबंध में राज्य व्यापार निगम खाद्य तेल खाता रखता है। खाद्य तेल खाते की वार्षिक लाभकारिता और वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान खाद्य तेल खाते में घाटे की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकार द्वारा रिलीज की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(राशि : करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाभकारिता (खाद्य तेल खाते में घाटा/अधिशेष)	घाटे के प्रति सरकार द्वारा की गई प्रतिपूर्ति
1994-95*	(+) 22.29	25.00
1995-96	(-) 57.95	100.00
1996-97	(-) 63.13	50.00
1997-98	(-) 30.00 (अनंतिम)	20.00

* 1.4.94 को स्थिति के अनुसार खाद्य तेल खाते में 61.66 करोड़ रुपए का घाटा था।

(घ) राज्य व्यापार निगम के खाद्य तेल में घाटे का कारण आयात किए गए तेल की लागत और इसकी बिक्री प्राप्तियों के बीच अन्तर है जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल के मूल्य, अमेरिकी डालर की रुपए में परिवर्तन दर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेलों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य और पैकिंग, दुलाई आदि संबंधी हैंडलिंग लागत जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है। खाद्य तेल खाते में घाटे को कम करने के लिए सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए आयातित खाद्य तेल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित करती रही है।

Distribution of foodgrains through TPDS

1847. SHRI A. VIJAYA RAGHVAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government will continue the TPDS system to help the families below poverty line;

(b) if so, the details of the distribution of foodgrains in different States under this programme; and

(c) the steps to be taken to improve this programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. Government will continue the Targeted Public Distribution System (TPDS) with its focus on the poor.

(b) State-wise details of allotment of foodgrains under TPDS are given in the statement at Annexure. [*See* Appendix 184, Annexure No. 59.] Details of cumulative allotment and offtake of wheat and rice under TPDS (including additional allocations) may be seen at the above mentioned.

(c) Streamlining of Public Distribution System is a continuous process and Government reviews this from time to time to meet the changing requirements.

Distribution of imported Palmolein Oil to States

1848. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that palmolein oil was imported by Government during the year 1996-97;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the palmolein oil was distributed to the States;

(d) whether Gujarat State was allotted less oil than other States;

(e) if so, the details of distribution to each State; and

(f) whether Gujarat State will be compensated therefor in future supply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) During the year 1996-97, the STC imported 1.49 lakh M.Ts. of RBD Palmolein of the CIF value of Rs. 300.20 crores on Government Account exclusively for the Public Distribution System (PDS).

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) The State of Gujarat was allocated 40,000 M.Ts. of RBD Palmolein during the year 1996-97. This allocation to Gujarat was the second highest allocation and constituted 20.74% of the total allocations made to the States/U.Ts. during that year.

(f) The allocation of RBD Palmolein to be made to the State of Gujarat, in future, will depend on the inter-se requirement of the States/U.Ts. the quantity of oil available for the PDS, pace of lifting of the previous allocation made to Gujarat etc.